



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 जून, 2023

पैलियो आहार के स्वास्थ्य संबंधी दावों को खारजि करना

पैलियो आहार ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य दावों और प्रभावकारिता के कारण समाचारों में ध्यान आकर्षित किया है। पैलियो आहार के समर्थकों का दावा है कि हमारे पूर्वजों के खान-पान का अनुसरण करने से लोगों को वजन कम करने में मदद मिल सकती है, साथ ही लंबी अवधि की बीमारी होने की संभावना कम हो सकती है। हालाँकि आलोचकों का तर्क है कि इन दावों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। यहाँ आहार डेयरी, अनाज, फलियाँ तथा प्रसंस्कृत शर्करा को छोड़कर असंसाधित खाद्य पदार्थ जैसे- सब्जियाँ, फल, नट्स तथा लीन मीट के सेवन पर जोर देता है। पैलियो आहार का वर्तमान संस्करण पारंपरिक आहार दिशा-निर्देशों की तुलना में कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन सेवन को दर्शाता है। वजन घटाने हेतु पैलियो आहार की पारंपरिक अनुशंसित आहार से तुलना करने वाले अध्ययनों में दो वर्षों के बाद प्रभावशीलता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। टाइप 2 मधुमेह पर आहार के प्रभाव के संबंध में समान अनरिणायक परिणाम देखे गए। इसके अलावा एक अध्ययन से पता चला है कि पैलियो आहार ने हृदय रोग से जुड़े पेट के जीवाणुओं की अधिकता को जन्म दिया, जो रोग की रोकथाम के दावों का खंडन करता है। पैलियो आहार खाने की योजना है जो उन प्राचीन मनुष्यों के आहार का अनुसरण करने पर जोर देता है जो पुरापाषाण युग में रहते थे। पैलियो आहार इस धारणा पर आधारित है कि हमारे जीन हमारे पूर्वजों के आहार के अनुकूल हैं एवं आधुनिक आहार हमारे जीव विज्ञान से बेमेल है। हालाँकि आनुवंशिक शोध इस धारणा का खंडन करते हैं। लैक्टोज पर अध्ययन (यह एंजाइम लैक्टोज को पचाने में मदद करता है, जो डेयरी उत्पादों में पाया जाता है) शराब के चयापचय में दृढ़ता एवं अनुकूलन से पता चलता है कि पैलियो आहार की तुलना में विकास बहुत कम समय-सीमा के भीतर हो सकता है।

और पढ़ें... [भारत की पोषण समस्या](#)

भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय करूज पोत एमवी एम्प्रेस

केंद्रीय पोत, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने चेन्नई से श्रीलंका के लिये भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय करूज पोत, एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में चेन्नई स्थित अंतरराष्ट्रीय करूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया जो [करूज पर्यटन](#) और समुद्री व्यापार के अवसरों को बढ़ाने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एमवी एम्प्रेस तीन श्रीलंकाई बंदरगाहों के लिये रवाना होगा: हनबंटोटा, त्रिफोमाली और कांकेस्तुरेई। करूज सेवा वर्ष 2022 में प्रथम अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय करूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मेसर्स वाटरवेज लीजर ट्रिजिम प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) का परिणाम है। सरकार [अंडमान, पुदुचेरी](#) और [लक्षद्वीप](#) में तीन नए अंतरराष्ट्रीय करूज टर्मिनल विकसित करने की योजना बना रही है जिनके वर्ष 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। सरकार ने करूज जहाजों की संख्या वर्ष 2023 के 208 से बढ़ाकर वर्ष 2030 में 500 और 1100 तक करने की कल्पना की है। वर्ष 2047 तक यात्रियों की संख्या वर्ष 2030 के 9.5 लाख से बढ़कर 45 लाख हो जाएगी।

और पढ़ें... [गंगा वलास करूज, भारत में करूज पर्यटन की संभावना](#)

भारत की IT ग्रोथ: पलिरस, ऑपरच्युनिटीज़ और फ्यूचर टेक इकोसिस्टम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत [सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया \(STPI\)](#) ने "भारतीय आईटी उद्योग के विकास के रास्ते और उभरते तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र" पर एक सेमिनार की मेज़बानी करके अपना 32वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में भारत के आईटी विकास में योगदान देने वाले छह स्तंभों पर प्रकाश डाला गया। इन स्तंभों में कनेक्टिविटी, कम लागत वाला डेटा, कफायती उपकरण, लोगों के अनुकूल नीतियाँ, भविष्य के लिये तैयार प्रतिभा और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त "इनोवेशन थ्रू एग्रीटेक: ए स्टडी ऑन एडॉप्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एग्री एंड एग्री-एलाइड सेक्टर" शीर्षक वाली एक एग्रीटेक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में एग्रीटेक की वर्तमान स्थिति, क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ तथा विकास एवं नवाचार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। STPI की स्थापना वर्ष 1991 में MeitY के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। STPI का मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर नरियात को बढ़ावा देना रहा है। [SPI](#) आईटी/आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (EHPT) योजना लागू कर रहा है।

और पढ़ें: भारतीय आईटी उद्योग, [एग्रीटेक](#)।

न्याय विकास पोर्टल

न्याय विकास पोर्टल [ज़िलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र परियोजना \(CSS\)](#) के न्याय विभाग के कार्यान्वयन का हिस्सा है, जो वर्ष 1993-94 से परचालन में है। इसे हतिधारकों को वित्तपोषण, दस्तावेज़ीकरण, परियोजना नगिरानी और अनुमोदन से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी तक नरिबाध पहुँच प्रदान करने के लिये विकसित किया गया है। इस CSS का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों, ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिये कोर्ट हॉल व आवासीय इकाइयों के नरिमाण में राज्य सरकारों और केंद्रशासति प्रदेशों के प्रशासन का समर्थन करना है। समय के साथ यह योजना वकीलों और वादियों के लिये सुविधा बढ़ाने के लिये लॉयर हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करने के लिये विकसित की गई है। योजना के तहत वित्तपोषण पैटर्न केंद्र सरकार और राज्य सरकारों (पूर्वोत्तर और हमिलयी राज्यों को छोड़कर) के बीच 60:40 के अनुपात का पालन करता है। उत्तर पूर्वी और हमिलयी राज्यों के लिये अनुपात 90:10 है, जबकि केंद्र शासति प्रदेशों को 100% राश प्र्राप्त होती है। न्याय विकास पोर्टल इस योजना के कार्यान्वयन की नगिरानी, पारदर्शति और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

और पढ़ें.. [न्यायपालिका के लिये आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास के लिये केंद्र परियोजना \(CSS\)](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-06-june-2023>

